भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3067
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के विरुद्ध वाहन विनिर्माता

3067. श्री ए के सेल्वाराज:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वाहन विनिर्माताओं ने सरकार से यह आग्रह किया है कि वह वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की अपनी योजना पर कार्यवाही न करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस हड़बड़ी से देश भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकियों के विकल्पों को बंद कर रहा है; और

(घ) क्या इस बात की व्यापक रूप से आलोचना हो रही है कि राष्ट्रव्यापी ई-कार योजना अच्छी योजना, कार्यनीति अथवा प्रौद्योगिकी की अपेक्षा आवेग पर अधिक आधरित है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग में वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग)और (घ): ऊपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****